



प्रधानमंत्री 25-26 अगस्त को  
गुजरात का दौरा करेंगे

गण्डीय हिन्दी दैनिक

# लोकशक्ति



थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र दिवेदी अल्जीरिया की  
राजकीय यात्रा पर रवाना हुए

RNI Regn. No.7789/1964

वर्ष-61 > अंक - 240

रायपुर सोमवार 25 अगस्त 2025 विक्रम संवत् 2082

पृष्ठ 8 मूल्य : 2 रु.

डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

अमित शाह ने किया अखिल भारतीय विधान सभा अध्यक्ष सम्मेलन का शुभारंभ, कहा :

## दलगत हितों से ऊपर उठ राष्ट्रहित का विचार ही लोकतंत्र की सर्वोच्च गरिमा

लोकतंत्र तभी फलता-फूलता है जब  
विधानसभा एवं विवेक, विचार और  
विधान के मूल मंत्र पर चलती हैं

नईदिल्ली, एजेंसी

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री  
अमित शाह ने आज दिल्ली विधानसभा में  
स्वतंत्रता संभाली विडुलभाई पटेल जी के  
केन्द्रीय विधानसभा के पहले निवारित  
भारतीय स्पीकर बनने के 100 वर्ष पूर्ण  
होने के उपलक्ष्य में आयोजित दो दिवसीय  
अखिल भारतीय विधान सभा अध्यक्ष  
सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर  
पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र  
गुप्ता, केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण  
रिजिजू, दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री विनय  
कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री  
श्रीमती रेखा गुप्ता सहित अनेक गणमान्य  
व्यक्ति उपस्थित थे।

इस सम्मेलन में राज्यों/केन्द्रशासित  
प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष,  
उपाध्यक्ष और विधान परिषदों के सभापति  
एवं उपसभापति हिस्सा ले रहे हैं। इस  
अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली



विधानसभा परिसर में विडुलभाई पटेल के  
जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का  
अवलोकन भी किया।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा  
पर विडुलभाई पटेल ने भारत की विधायी  
परिवारों की नींव रखकर आज के

लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य किया।  
उन्होंने कहा कि भारतीय विधायी के आधार  
पर लोकान्त्रिक ढंग से देश को चलाने की  
नींव डालने का कार्य यदि किसी ने कहा  
तो वह निस्संदेह वीर विडुलभाई पटेल थे।

विडुलभाई पटेल ने कहा कि विधायी का  
प्रतिष्ठान और सभापति का नियमित विधायी  
कार्यक्रम का नियमित विधायी का नियमित

यदि संसद और विधानसभाओं के  
गलियारों में वार-विवाद नहीं होगा, तो  
वे केवल एक निर्जीव भवन बनकर रह  
जाएंगे : अमित शाह

गृह मंत्री ने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष  
से इस ऐतिहासिक सदन में सभी  
महानुभावों द्वारा दिए गए भाषणों का  
संकलन देश की सभी विधानसभाओं के  
पुरस्कारों में उपलब्ध कराने का  
आग्रह किया।

स्थापित करने का कार्य किया, जो आज  
हम सभी के लिए, विशेषकर विधायी कार्यों  
और सभापति के दायित्वों के लिए,  
ज्योतिर्मय दीपक की तरह मार्गदर्शन कर  
रही है। श्री शाह ने कहा कि विडुलभाई  
पटेल के सामने कई बार परीक्षा की घड़ी  
आई, परंतु प्रत्येक परीक्षा में वे शत-प्रतिशत  
उत्तीर्ण हुए। उन्होंने न तो विधानसभा  
अध्यक्ष की गरिमा को कम होने दिया, न ही  
इस सदन को देश की आवाज दबाने से  
रोका, और न ही अंग्रेजों की तत्कालीन  
मानसिकता को विधानसभा के कार्यों पर  
हावी होने दिया।

अब वॉट्स-एप-ईमेल पर  
मिलेगा कोर्ट का समन और  
वारंट, सरकार ने लागू किया  
नया नियम

नई दिल्ली । एजेंसी

दिल्ली सरकार ने समन और  
गिरफ्तारी वारंट की तापील को  
लेकर बड़ा बदलाव किया है।  
अब अदालत का समन और  
वारंट लोगों को मोबाइल पर  
व्हाट्स-एप और ईमेल के जरिए  
भेजा जा सकेगा। इसके लिए  
सरकार ने नियम बीएन-एसएस  
(समन और वारंट की तापील)  
नियम, 2025 अधिसूचित कर  
दिए हैं। जानकारी के मूलायिक,  
सरकार के इस फैसले से मिनटों  
में समन की डिलीवरी संभव हो  
जाएगी और समय व कागजी  
प्रक्रिया की बचत होगी। इस  
परीक्षण को उपराज्यपाल  
विनय कुमार सक्सेना ने वहां पर  
मंजूरी दे चुके हैं। नई व्यवस्था  
के तहत अदालतों द्वारा जारी समन  
और वारंट पर जज की डिजिटल  
मुहर और हस्ताक्षर होंगे। पुलिस  
संबंधित व्यक्ति को ईमेल या  
व्हाट्स-एप पर वह नोटिस भेजेगी।  
यदि तकनीकी कारणों से उन्हें  
तो कोर्ट हाई कॉर्पी देने का  
निर्णय दे सकती है। इसके लिए  
पुलिस थानों में इलेक्ट्रॉनिक  
समन वितरण केंद्र भी बनाए  
जाएंगे।

भारत में बने एयर डिफेंस  
सिस्टम का सफल परीक्षण



नई दिल्ली एजेंसी।

भारत ने एक बड़ी उपलब्धि  
हासिल करते हुए इंटरेंटेड एयर  
डिफेंस हथियार प्रणाली  
(आईएडब्ल्यूएस) का सफल  
विनाय कुमार सक्सेना ने लिए बाहर  
देता है। यह अनूठा उड़ान परीक्षण  
हमारे देश की बहु-स्तरीय एयर  
डिफेंस क्षमता को स्पाफित करता  
है। यह महत्वपूर्ण स्थानों की  
शामिल है। इस महत्वपूर्ण परीक्षण  
पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह  
सिंह ने कहा कि आईएडब्ल्यूएस के  
उपलब्धि भारत के लिए बहाई  
देता है। यह अनूठा उड़ान परीक्षण  
हमारे देश की बहु-स्तरीय एयर  
डिफेंस क्षमता को उन्नीस एसएस  
जॉनरल एडब्ल्यूएस के प्रति  
जिनके पास आधुनिक, स्वदेशी  
और बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली  
मौजूद है। आईएडब्ल्यूएस एक  
रक्षा क्षमता को उन्नीस एसएस भेजेगी।  
यह महत्वपूर्ण स्थानों की ब्रह्मगंगा  
देशों की श्रेणी में शामिल करती है।  
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि  
जिनके पास आधुनिक, स्वदेशी  
और बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली  
मौजूद है। आईएडब्ल्यूएस एक  
रक्षा क्षमता को उन्नीस एसएस भेजेगी।  
यह महत्वपूर्ण स्थानों की ब्रह्मगंगा  
देशों की श्रेणी में शामिल करती है।  
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि  
जिनके पास आधुनिक, स्वदेशी  
और बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली  
मौजूद है। आईएडब्ल्यूएस एक  
रक्षा क्षमता को उन्नीस एसएस भेजेगी।  
यह महत्वपूर्ण स्थानों की ब्रह्मगंगा  
देशों की श्रेणी में शामिल करती है।  
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि  
जिनके पास आधुनिक, स्वदेशी  
और बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली  
मौजूद है। आईएडब्ल्यूएस एक  
रक्षा क्षमता को उन्नीस एसएस भेजेगी।  
यह महत्वपूर्ण स्थानों की ब्रह्मगंगा  
देशों की श्रेणी में शामिल करती है।  
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि  
जिनके पास आधुनिक, स्वदेशी  
और बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली  
मौजूद है। आईएडब्ल्यूएस एक  
रक्षा क्षमता को उन्नीस एसएस भेजेगी।  
यह महत्वपूर्ण स्थानों की ब्रह्मगंगा  
देशों की श्रेणी में शामिल करती है।  
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि  
जिनके पास आधुनिक, स्वदेशी  
और बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली  
मौजूद है। आईएडब्ल्यूएस एक  
रक्षा क्षमता को उन्नीस एसएस भेजेगी।  
यह महत्वपूर्ण स्थानों की ब्रह्मगंगा  
देशों की श्रेणी में शामिल करती है।  
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि  
जिनके पास आधुनिक, स्वदेशी  
और बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली  
मौजूद है। आईएडब्ल्यूएस एक  
रक्षा क्षमता को उन्नीस एसएस भेजेगी।  
यह महत्वपूर्ण स्थानों की ब्रह्मगंगा  
देशों की श्रेणी में शामिल करती है।  
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि  
जिनके पास आधुनिक, स्वदेशी  
और बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली  
मौजूद है। आईएडब्ल्यूएस एक  
रक्षा क्षमता को उन्नीस एसएस भेजेगी।  
यह महत्वपूर्ण स्थानों की ब्रह्मगंगा  
देशों की श्रेणी में शामिल करती है।  
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि  
जिनके पास आधुनिक, स्वदेशी  
और बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली  
मौजूद है। आईएडब्ल्यूएस एक  
रक्षा क्षमता को उन्नीस एसएस भेजेगी।  
यह महत्वपूर्ण स्थानों की ब्रह्मगंगा  
देशों की श्रेणी में शामिल करती है।  
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि  
जिनके पास आधुनिक, स्वदेशी  
और बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली  
मौजूद है। आईएडब्ल्यूएस एक  
रक्षा क्षमता को उन्नीस एसएस भेजेगी।  
यह महत्वपूर्ण स्थानों की ब्रह्मगंगा  
देशों की श्रेणी में शामिल करती है।  
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि  
जिनके पास आधुनिक, स्वदेशी  
और बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली  
मौजूद है। आईएडब्ल्यूएस एक  
रक्षा क्षमता को उन्नीस एसएस भेजेगी।  
यह महत्वपूर्ण स्थानों की ब्रह्मगंगा  
देशों की श्रेणी में शामिल करती है।  
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि  
जिनके पास आधुनिक, स्वदेशी  
और बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली  
मौजूद है। आईएडब्ल्यूएस एक  
रक्षा क्षमता को उन्नीस एसएस भेजेगी।  
यह महत्वपूर्ण स्थानों की ब्रह्मगंगा  
देशों की श्रेणी में शामिल करती है।  
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि  
जिनके पास आधुनिक, स्वदेशी  
और बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली  
मौजूद है। आईएडब्ल्यूएस एक  
रक्षा क्षमता को उन्नीस एसएस भेजेगी।  
यह महत्वपूर्ण स्थानों की ब्रह्मगंगा  
देशों की श्रेणी में शाम





## संपादकीय

### बेबुनियादी आरोपों की जांच होना आवश्यक

क्या राहुल गांधी अपने बेबुनियादी आरोपों के सहारे बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर राहुल गांधी जिस वक्त वोट चारों का आरोप लगाते हुए आरोप मढ़ रखे थे, ठीक उसी वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त जानेश कुमार दिल्ली में जबवाबी कार्रवाई का ऐलान कर रहे थे? उन्होंने प्रेस कॉफेस के माफत से कर्मचारियों की झैंगनदारी पर हमला बताया। आयोग राहुल के सवालों का जवाब देते हुए आरोपों को एपिक संभाल मिलती-जुलती है। जिसके सज्जन में इनकी जांच नहीं होने की बात करते हुए ज्ञानेश ने आते ही बदलाव किया गया।



### रुखसार का तेरे असर कुछ ऐसा,

आँखों से झलकता इक मय-खाना।  
तेरी जुल्कों में बसा इक आशियाना।

तेरी जुल्कों की छाँव में सुकून पाया,  
जख्मों को भूलकर तुझे अपनाया।

जुल्कों में जुगनुओं का बोलबाला,  
इन आँखों से गैंशन मेरा सरमाया।  
(सरमाया-पूजा, दैलत)

तेरे चेहरे पे जब जुल्के बिखर जाती  
चाँद भी देख तुझे लज्जा से शरमाया।

जुल्कों की सलामती दुआ करता हूँ  
साथे में इस्के मैंने जनत को पाया।

रुखसार का तेरे असर कुछ ऐसा,  
जुल्कों में ही खोकर सारा जहाँ पाया।

(रुखसार- गाल, सुंदर चेहरा, )

- संजीव ठाकुर।

## ( संपादकीय + संदेश )

### अग्रिमनोज

डिजिटल क्रांति ने दुनिया को जोड़ने के साथ ही अपराध की दुनिया को भी बिना सीमाओं वाला बना दिया है। भारत में उत्तर प्रदेश सरकार का हालिया कदम-डाटा चोरी पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, इस चुनौती से निपटने की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है। लेकिन इस पहल का महल्के केवल एक राज्य या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर के साइबर कानूनों और न्याय व्यवस्था की बड़ी बहस का हिस्सा है। भारत में यह चर्चा ऐसे समय हो रही है कि जब यूरोप और अमेरिका पहले से ही डाटा सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर कड़े कदम उठा चुके हैं। यूरोपियन यूनियन का GDPR (General Data Protection Regulation) आज पूरी दुनिया में मानक बन चुका है, जिसमें कंपनियों पर अखों यूरोप तक का जुर्माना लगाने की क्षमता है। वहाँ, अमेरिका में California Consumer Privacy Act (CCPA) और हाल ही में बने संघीय स्तर पर प्रस्तावित American Data Privacy Protection Act (ADPPA), नागरिकों की डाटा सुरक्षा को अधिक व कानूनी तकत से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में 250 करोड़ रुपये तक की जुर्माना का प्रस्तावित प्रावधान केवल जुर्माना नहीं, बल्कि एक मानसिक बदलाव का संकेत है। यह भारत को यूरोप और अमेरिका की पांक में खड़ा करता है, लेकिन अपनी सामाजिक-आधिक परिस्थितियों और पर्सिस्क-आधारित कानून प्रवर्तन की वजह से यह -भारतीय मॉडल- अलग राह दिखाता है। अगले कुछ वर्षों में यह मॉडल यदि सफल हुआ तो भारत वैश्विक स्तर पर +साइबर लॉ इनोवेशन- का नया केंद्र बन सकता है।

भारत की गाह क्यों अलग है?

भारत की समस्या यूरोप और अमेरिका से अलग है।

यहाँ न केवल कंपनियों बल्कि छोटे साइबर कैफे, लोकल सर्विस प्रोवाइडर, ऐप डेवलपर और यहाँ तक कि शैक्षिक संस्थान तक डाटा लीक के केंद्र बन सकते हैं। भारत को कानून बनाने समय यह देखना होगा कि कठोर जुर्माना केवल +डाटा+ पैदा न करे, बल्कि सिस्टम को सुरक्षित बनाने का स्थायी ढांचा दैवत रकरे।

यूरोपी का कदम इस मायने में अलग है कि यह कानून प्रवर्तन और पर्सिस्क साइबर के केंद्र में खत्म हो। यूरोप और अमेरिका जहाँ निगरानी एजेंसियों व न्यायालय पर भरोसा करते हैं, वहाँ भारत में +फर्सिस्क ऑडिट+ और +मोबाइल फॉरेंसिक वैन- जैसे उपयोग अनोखे प्रयोग हैं। यह भारतीय संदर्भ में अधिक व्यावहारिक साबित हो सकता है।

साइबर युद्ध का नया दौर

साइबर अपराध अब केवल चोरी या धोखाधड़ी का

मामला नहीं रहा। यूरोपियन यूनियन की संसद और अमेरिकी चुनावों पर हैकिंग देते से यह सफल है कि साइबर क्राइम -यांत्रीय सुरक्षा- से जुड़ा हुआ है। भारत में भी हाल ही में AI-आधारित फिल्म अटेक, बैंकिंग ट्रोजन और सोशल इंजीनियरिंग के मामलों में तेजी आई है।

इस संदर्भ में 250 करोड़ का जुर्माना केवल +आधिक दंड- नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि भारत अब साइबर अपराध को +आम अपराध- नहीं बल्कि +रणनीतिक अपराध+ मानकर उससे पिण्ठेगा।

डाटा ऑडिट: जैसे वित्तीय ऑडिट होता है, वैसे ही कंपनियों के लिए नियमित डाटा ऑडिट अनिवार्य किया जाना चाहिए।

डिजिटल इंश्योरेंस: डाटा चोरी और साइबर हमलों से बचाव होने की कंपनियों और व्यक्तियों के लिए बीमा योजनाएं आवश्यक होंगी।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत को यूरोप और अमेरिका की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराधियों के प्रत्यर्पण और खुफिया साझेदारी को मजबूत करना होगा।

भारत का साइबर फ्रॉन्टियर और कानूनी सभी

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट, 2000) और हाल ही में बने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटोकल एक्ट, 2023 डाटा सुरक्षा का आधार प्रदान करते हैं। परंतु इन कानूनों की व्यावहारिक चुनौती यह है कि इनके तहत अभी तक दंड और जुर्माने का ढांचा यूरोप-अमेरिका की तरह भयभीत करने वाला नहीं रहा। यूरोपी सरकार द्वारा सुरक्षा यथा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना इस लिहाज से एक मिसाल बन सकता है कि भारत अब केवल चेतावनी तक सीमित न रहकर दड़ामत्क कठोरता की ओर बढ़ रहा है।

कानूनी दृष्टि से GDPR न केवल सुरक्षा, बल्कि +डाटा अधिकार+ को भी नागरिकों के मौलिक अधिकार की तरह मान्यता देता है।

अमेरिका (CCPA ADPPA) -

अमेरिका का मॉडल यूरोप की तरह केंद्रीकृत और कठोर है, बल्कि राज्य-स्तरीय कानूनों पर आधारित है।

कैलिफोर्निया का CCPA उपरोक्ताओं को कंपनियों से यह पूछने का अधिकार देता है कि उनका डाटा किस उद्देश्य से यह पूछने का अधिकार देता है कि उनका डाटा किस उद्देश्य से यह पूछने का अधिकार देता है कि उनका डाटा किस उद्देश्य से यह पूछने का अधिकार देता है।

हालांकि अमेरिका में जुर्माने की सीमा यूरोप जितनी

कानूनी विलेखण: यूरोप बनाम अमेरिका बनाम भारत यूरोप (GDPR मॉडल) -

GDPR किसी भी कंपनी को जो यूरोपियन नागरिकों का

डाटा प्रोसेस करती है, 20 मिलियन यूरो या प्रि उनकी

कुल वार्षिक वैश्विक आय का 4% तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है।

इसका प्रभाव यह हुआ कि फेसबुक, गूगल और अमेरिजन जैसी दिग्जिटल कंपनियों को अखों डॉलर के जुर्माने चुकाने पड़।

कानूनी दृष्टि से GDPR न केवल सुरक्षा, बल्कि +डाटा अधिकार+ को भी नागरिकों के मौलिक अधिकार की तरह मान्यता देता है।

अमेरिका (CCPA ADPPA) -

अमेरिका का मॉडल यूरोप की तरह केंद्रीकृत और कठोर है, बल्कि राज्य-स्तरीय कानूनों पर आधारित है।

कैलिफोर्निया का CCPA उपरोक्ताओं को कंपनियों से यह पूछने का अधिकार देता है कि उनका डाटा किस उद्देश्य से यह पूछने का अधिकार देता है कि उनका डाटा किस उद्देश्य से यह पूछने का अधिकार देता है।

यह पूछने का अधिकार देता है कि उनका डाटा किस उद्देश्य से यह पूछने का अधिकार देता है।

यह पूछने का अधिकार देता है कि उनका डाटा किस उद्देश्य से यह पूछने का अधिकार देता है।

यह पूछने का अधिकार देता है कि उनका डाटा किस उद्देश्य से यह पूछने का अधिकार देता है।

यह पूछने का अधिकार देता है कि उनका डाटा किस उद्देश्य से यह पूछने का अधिकार देता है।

यह पूछने का अधिकार देता है कि उनका डाटा किस उद्देश्य से यह पूछने का अधिकार देता है।

यह पूछने का अधिकार देता है कि उनका डाटा किस उद्देश्य से यह पूछने का अधिकार देता है।

यह पूछने का अधिकार देता है कि उनका डाटा किस उद्देश्य से यह पूछने का अधिकार देता है।

यह पूछने का अधिकार देता है कि उनका डाटा किस उद्देश्य से यह पूछने का अधिकार देता है।

यह पूछने का अधिकार देता है कि उनका डाटा किस उद्देश्य से यह पूछने का अधिकार देता है।







## एनएचएम के संविदा कर्मचारियों के हड्डताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर वितरित असर

रायपुर। ग्रामीय स्वास्थ्य सेवामिशन के कमंचारी इस समय विभिन्न मार्गों को लेकर हड्डताल पर हैं। ये संविदा कर्मी हड्डताल पर चले गए हैं जिसके कारण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में विपरीत असर पड़ रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के ग्रामीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत कर्मचारी दस सूचीय मार्गों को लेकर आंदोलन धर्मा देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने खुन से एक पत्र मुख्यमंत्री से लिखा है। इनको मार्ग है कि इन्हें इनका संविदा नियम किया जाए तथा 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि ग्रेड पे निर्धारण और पब्लिक हेल्थ क्रेडर की स्थापना की जाए।

संघ के अध्यक्ष डॉ. अमित ने बताया कि हड्डताल शुरू होने के बाद स्वास्थ्य मत्री से मुलाकात कर सभी प्रमुख मार्ग पूरी करने की मार्ग की गई है लेकिन अभी तक काई हल नहीं निकला है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में काफी



## मुख्यमंत्री ने जापान में एनटीटी लिमिटेड की सीईओ से की मुलाकात

टोक्यो/रायपुर। मुख्यमंत्री ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हुई एक अहम मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में टिकटोर) पर साझा करते हुए लिखा। टोक्यो में एनटीटी लिमिटेड, जापान की सीईओ सुश्री कायो इतो से मुलाकात हुई। इन्होंने जिलियम रेलवे के साथ यह कंपनी वैश्विक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को गति देने, युवाओं के लिए तकनीक-आधारित निवेश की सम्भावनाओं पर मुख्यमंत्री की अग्रणी कंपनी हो गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ में डिजिटल और एडवांस टेक्नोलॉजी आधारित निवेश पर सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री की टोक्यो में हड्डताल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य सरकार की लिमिटेड, जापान की सीईओ सुश्री कायो इतो से यह महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। एनटीटी लिमिटेड एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है, जो दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

## छत्तीसगढ़ में सिंतंबर आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज बंद

रायपुर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने घोषणा की है कि 1 सिंतंबर से प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कैशलेस इलाज की सुविधा रोक दी जाएगी। आगे सरकार सही ब्रॉक पर फैसला नहीं लेती है तो छत्तीसगढ़ के गोरी जनता को इलाज के लिए दो-चार होना पड़ेगा। साथ ही निहायत जरुरी स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम होना भी पड़ सकता है, जबकि छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज की सुविधा जल्द ही बंद हो सकती है।

### अस्पतालों को छह महीने से भुगतान

आईएमए ने बताया कि यह फैसला लंबे समय से अस्पतालों को योजना के तहत इलाज का भुगतान नहीं मिलने के कारण लिया गया। सिंतंबर से प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कैशलेस इलाज की सुविधा रोक दी जाएगी। इस फैसले का सबसे बड़ा प्रभाव उन गोरी और मध्यमवर्गीय परिवारों पर होगा, जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज करते हैं। कई मरीज इस योजना पर निर्भर हैं और उन्हें अब अस्पताल में कैशलेस सुविधा न मिलने के कारण सीधे भुगतान करना पड़ सकता है।

### संनिधि समाधान नहीं हुआ तो इलाज नुरिकल

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो राज्य में गोरी भरीजों के लिए इलाज की मुहूंच पर गोरी अस्पतालों की आर्थिक स्थिती भी योजना के नियमित भुगतान न मिलने के कारण प्रभावित हो रही है।

### 1 सिंतंबर से पहले हो जाएगा भुगतान - मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि निजी अस्पतालों को 1 सिंतंबर का इलाज नहीं करना होगा। 1 सिंतंबर से पहले निजी अस्पतालों को पेंटेंट कर देंगे। निजी अस्पतालों को जुलाई तक का पेंटेंट 2-3 दिन के भीतर कर दिया जाएगा।

# रायपुर पुलिस ने जब्त किया 57 लाख रुपये की मात्रता का हेरोइन, 6 आरोपी गिरफ्तार



जाने मुख्यमंत्री द्वारा बताये हुए लोगों के व्यक्ति की पतासाजाँ कर चिन्हकित कर फकड़ा गया, पूछताल में व्यक्ति ने अपना नाम मनोहरन सिंह संहेद्री उर्फ जय तथा स्वास्थ्य मिशन 6 सदस्यों वे मिशनपात्री एवं भूषण शर्मा सहित 6 सदस्यों द्वारा प्रयुक्त की त्रैमात्रीक गठन की टीम को गठित किया गया। विशेष टीम के द्वारा हेरोइन(चिन्ह) तथा घटना में प्रयुक्त 01 नगर दोपहिया वाहन एवं 05 नगर मोबाइल फोन खुदरा मूल्य कीमती लगभग 57,00,000 रुपये जस कर आरोपियों के विरुद्ध थाना कीवर नगर में धारा 21बी, 21सी, 29 एन.डी.पी.एस एक्ट तथा 111 बीएनस के तहत अपराध जंजीबद कर कार्यवाली किया गया है। इसी प्रकार थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 165/25 मार्ग के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त की त्रैमात्रीक गठन की टीम के द्वारा हेरोइन(चिन्ह) के संबंध में कांडी से पूछताल करने हुए विशेष टीम के गठन किया गया। विशेष टीम के द्वारा हीरापुर थाना कीवर नगर, जरावर तालव के पास स्थित मकान तथा अरटीए बॉलोनी में एकसाथ रेड कार्यवाली कर आरोपी मिशनपात्र सिंह संधू उर्फ जयगु जामकर खाली तरफ देखते हुए देखते हैं जिसे वह यह अपने डिस्ट्रीब्यूटर विजय मोटवानी, भूषण शर्मा को देता था तथा वे लोग अन्य लोगों को देते थे। जिस पर मनोहरन सिंह संधू उर्फ जयगु से विजय मोटवानी से हेरोइन(चिन्ह) पाया गया। जिस पर टीम के द्वारा तालवा लेने पर उनके मकान में कांडी से देखते हुए देखते हैं जिसे वह यह अपने डिस्ट्रीब्यूटर विजय मोटवानी, भूषण शर्मा को देता था तथा वे लोग अन्य लोगों को देते थे। जिस पर मनोहरन सिंह संधू उर्फ जयगु से विजय मोटवानी से हेरोइन(चिन्ह) पाया गया।

## मुख्यमंत्री साय का जापान प्रवास: छत्तीसगढ़ के लिए तकनीक, व्यापार और संस्कृति के नए आयाम

### वैश्विक नंग पर छत्तीसगढ़ - मुख्यमंत्री श्री साय का जापान दैरा बना तकनीकी और औद्योगिक सहयोग का सेतु

रायपुर। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ की भागीदारी से पूर्व मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 22 अगस्त को टोक्यो प्रवास की शुरूआत आध्यात्मिकता, तकनीक और व्यापार कैटर्नीक के संगम के साथ की।

टोक्यो पहुंचते ही मुख्यमंत्री श्री साय ने ऐतिहासिक अयाकूसा मंदिर के दर्शन किए। यह टोक्यो का सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित वार्षिक आयोग ने अपने उर्फ जयगु से विशेष टीम को गठित किया गया। विशेष टीम के द्वारा हेरोइन(चिन्ह) के संबंध में कांडी से पूछताल करने हुए विशेष टीम के गठन किया गया। विशेष टीम के द्वारा हीरापुर थाना कीवर नगर, जरावर तालव के पास स्थित मकान तथा अरटीए बॉलोनी में एकसाथ रेड कार्यवाली कर आरोपी मिशनपात्र सिंह संधू उर्फ जयगु की पती जसपाल मोटवानी के देखते हुए देखते हैं जिसे वह यह अपने डिस्ट्रीब्यूटर विजय मोटवानी, भूषण शर्मा को देता था तथा वे लोग अन्य लोगों को देते थे। जिस पर मनोहरन सिंह संधू उर्फ जयगु से विजय मोटवानी से हेरोइन(चिन्ह) पाया गया।



मुख्यमंत्री श्री साय और प्रतिनिधिमंडल ने इंडोपीस एक्ट के सदस्यों में छत्तीसगढ़ की टीम को गठित किया। यह टोक्यो का सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित वार्षिक आयोग है और ज्यानी विशेष टीम को जापान के दूसरे एक्सपो में इंडो-प्रैसिपिक देशों को उद्घाटन करते हुए विशेष टीम के द्वारा प्रयुक्त की त्रैमात्रीक गठन की टीम को गठित किया गया। इस विशेष टीम के द्वारा हेरोइन(चिन्ह) के संबंध में कांडी से पूछताल करने हुए विशेष टीम के गठन किया गया। विशेष टीम के द्वारा हीरापुर थाना कीवर नगर, जरावर तालव के पास स्थित मकान तथा अरटीए बॉलोनी में एकसाथ रेड कार्यवाली कर आरोपी मिशनपात्र सिंह संधू उर्फ जयगु की पती जसपाल मोटवानी के देखते हुए देखते हैं जिसे वह यह अपने डिस्ट्रीब्यूटर विजय मोटवानी, भूषण शर्मा को देता था तथा वे लोग अन्य लोगों को देते थे। जिस पर मनोहरन सिंह संधू उर्फ जयगु से विजय मोटवानी से हेरोइन(चिन्ह) पाया गया।

### सायमांकित रिश्तों और व्यापारिक साइंदेवारी को मजबूती देता है

सूचना प्रौद्योगिकी में नवाचारी की दिशा

में कदम : मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एनटीटी लिमिटेड की मुख्य

समाजीकरणीकरण की दिशा

में कदम : मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एनटीटी लिमिटेड की मुख्य

समाजीकरणीकरण की दिशा

में कदम : मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एनटीटी लिमिटेड की मुख्य

समाजीकरणीकरण की दिशा

में कदम : मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एनटीटी लिमिटेड की मुख्य